SHRI ANAND SHARMA : Sir, if I can answer...

MR. CHAIRMAN : I think we are derailing the discussion. The question is very specific. Let us not go into general discussion.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय सभापति जी, ...**(व्यवधान)**... मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से शुगर एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, आपको मालूम है कि शुगर एक्सपोर्ट का डिसीज़न न लिए जाने के कारण देश में किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है और देश में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आपकी बैठक में निर्णय नहीं होता है। आपने कपास के बारे में तो निर्णय ले लिया और कपास एक्सपोर्ट आपने खोल दिया, लेकिन शुगर एक्सपोर्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं खोल रही है। देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शुगर मिलों के सामने भी और गन्ना किसानों के सामने भी और इसमें हमारा स्टेट बहुत प्रभावित है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताएँगे कि शुगर एक्सपोर्ट पर आप कब निर्णय ले लेंगे? उस निणर्य की स्पष्ट घोषणा आप कब करेंगे, जिससे कि शुगर एक्सपोर्ट हो और चीनी मिल गन्ना किसानों को भुगतान कर सकें?

श्री आनन्द शर्मा : सर, मैं आपके माध्यम से शुगर एक्सपोर्ट के बारे में माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि इस पर एक मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट का निर्णय ले लिया गया है। चीनी के बारे में जो रिलीज ऑर्डर है, वह Ministry of Food and Consumer Affairs से आता है, जैसे ही वह ऑर्डर हमारे मंत्रालय को मिलेगा, DGFT को मिलेगा, शुगर के एक्सपोर्ट के निर्णय को तुरंत implement किया जाएगा।

श्री नरेश अग्रवाल : सर, इसको जल्दी कराया जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : नहीं, नहीं, नरेश जी, आपने अपना सवाल पूछ लिया। अब हो गया।

Poor construction of roads by BRO

*362. SHRI RAM KRIPAL YADAV : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Border Roads Organisation (BRO) is not maintaining quality of work in construction of roads, especially in Border areas, as recently constructed Nauti Khud Bridge by BRO on Dhami-Kingal road in Himachal Pradesh has collapsed/overturned;

(b) whether bituminous layer (renewal coat) laid two months before on Hapoli-Sarli-Huri road in Arunachal Pradesh has started deteriorating as pot holes are seen on renewed surface; and

(c) if so, whether Government proposes to investigate the matter?

THE MINISTER OF STATE IN MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU) : (a) No, Sir. This cannot be generalized.

Court of Inquiry regarding collapse of Nauti Khud Bridge has been held, disciplinary action against concerned officers initiated and contractor has been directed to construct the bridge afresh at his own risk and cost.

(b) No, Sir. A few patches have been damaged due to sudden rain while laying the renewal coat and are being repaired.

(c) Yes, Sir. Commander Task Force has investigated the matter and found that damage in patches is not due to poor quality of construction but due to following:

(i) Inclement weather condition throughout the year.

(ii) Sun shadow/wet patches on the road due to which road surface deteriorates faster.

(iii) Unauthorized quarrying all along the road by locals.

(iv) Cutting down of trees by local people along the road.

(iv) Tampering with drainage system of the road by blocking side drains and directing water to the fields for irrigation by local people through the road surface.

श्री राम कृपाल यादव : सर, खास तौर पर यह प्रश्न अपने आपमें गंभीर है, क्योंकि जो सीमा से जुड़ा हुआ सड़क है, वह देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। वहां सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हो, वहां एक पुल का निर्माण हो और वह पुल ध्वस्त हो जाए, तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए एक चिंता का विषय है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि ऐसी जगहों पर चूंकि proper monitoring नहीं होती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि वहां पर सड़कों या पुलों के निर्माण में अच्छी quality का सामान यानी सीमेंट, चिप्स, आदि नहीं लगाया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण इस तरह की घटिया सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है।

आपने इस बात को स्वीकारा है कि पुल ध्वस्त हो गया, सड़क भी ध्वस्त हो गई और इसके लिए आपने जांच भी बिठाई है। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो नौटी खुद पुल ध्वस्त हुआ, इसके निर्माण में कितनी राशि दी गई थी? आपने इसकी जांच के लिए जो कार्रवाई की है, इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसकी जांच कब तक पूरी हो जाएगी? आप संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई करेंगे और ठेकेदारों को क्या punishment देंगे तथा भविष्य में यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि किसी contractor और अधिकारी की मिलीभगत से इस तरह का घटिया काम दोबारा न हो?

SHRI M.M. PALLAM RAJU : Sir, at the outset, I would like to reassure the House that utmost importance is given to the quality of construction as far as Border Roads Organisation is concerned. As far as this specific supplementary is concerned, this 45-metre single span bridge, which was constructed by a contractor at a cost of Rs.2.48 crores, did collapse, and the Court of Inquiry determined and identified that this had happened due to an oversight in the design and also because of supervision errors. And the contractor has been asked to rebuild the bridge at his own cost. Apart from that, amongst other measures that we are taking to ensure good quality of roads and bridges all over the country, especially, in the remote areas and the border roads, the measures that we are taking is that we have a very senior officer at the level of the

Director, in each of these projects, to supervise the quality of construction, and an Executive Engineer-level officer, in each of the Task Forces, to also supervise the quality of the work. Also, supervision is carried out by the Border Roads Development Board which routinely monitor the quality of the work in each of these areas. So, there is a lot of emphasis on the quality of the works. In fact, if you go to the North-Eastern States, there is a preference by all the States that work is done by the Border Roads Organisation. So, that speaks a lot for the quality of works done by the Border Roads Organisation.

श्री राम कृपाल यादव : सर, इन्होंने कहा कि हम सड़कों का निर्माण बिल्कुल मापदंड के अनुसार करते हैं। मंत्री जी पता नहीं इसको स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे यह जानकारी है कि सामग्री की जो खरीद होती है, जैसे सीमेन्ट की खरीद होती है, तो इसकी लाइफ छ: महीने की होती है, लेकिन ये उसकी खरीद इतने huge amount में करते हैं कि वह सीमेन्ट चार-पाँच साल तक चलता रहता है, जबकि उसकी लाइफ छ: महीने के बाद कम हो जाती है। सर, इसी प्रकार, चिप्स वगैरह की क्वालिटी ठीक नहीं है।

माननीय मंत्री जी, जैसा कि आपने कहा कि आप इस पर निगरानी रखते हैं, जबकि इस पुल के संबंध में proper निगरानी नहीं हुई, जिसकी वजह से यह पुल ध्वस्त हो गया। सर, आम तौर से सीमा से जुड़ी हुई जो सड़क है, उसकी अहमियत है और मुझे तो यह भी जानकारी है कि सीमा सुरक्षा के लिए जिन सड़कों का निर्माण होता है, वह time bound होता है, जबकि वह उससे पास कर जाता है। निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने की वजह से उसकी cost में भी बढ़ोतरी होती है और उसकी क्वालिटी तो आपको नजर आ ही रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन सीमा सड़कों पर आप काम करा रहे हैं, खास तौर पर चाइना के threat को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में चाइना से जुड़ा हुआ हमारे देश का जो सीमावर्ती इलाका है, वहाँ जो रोड्स नहीं बन पा रही हैं, वे कब तक बन पाएँगी, क्योंकि इस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? क्या आपने इसके लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम रखा है? पूरे देश के पैमाने पर सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है, उन पर vigilance रखने के लिए क्या आपने उड़न दस्ते के रूप में कोई विशेष व्यवस्था की है, ताकि जो काम हो रहा है उसकी वह proper निगरानी कर सके और जहाँ गड़बड़ी हो, उसे वह काम होते वक्त ही रोकने का काम कर सके?

SHRI M. M. PALLAM RAJU : Sir, specifically, with reference to the Border Roads that the hon. Member has referred to, out of a total of 3394 kms, initial work has been done on about 2579 kms' length, while surfacing work has been completed on 1851 kms. Out of the 61 roads that he is alluding to, till date, 16 roads with a total length of 586 kms have been completed and we are in progress on the remaining 43 roads and we are making good progress on these roads.

श्री राम कृपाल यादव : सर, अपने क्वैश्चन के पार्ट टू में मैंने जो vigilance रखने की बात कही, उसका जवाब नहीं आया।

श्री सभापति : नहीं, आपका हो गया।

श्री राम कृपाल यादव : सर, जवाब नहीं आया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस तरह की सड़कों का फिर निर्माण होता रहेगा, उस पर proper निगरानी नहीं रखी जाएगी, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : अगर आप इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो...

श्री राम कृपाल यादव : सर, सरकार को assure करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Please, one minute. ...(*Interruptions*)... One at a time please.

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है, जो बड़े ही संघर्ष के साथ काम करती है, इसलिए इस विषय पर पूरा डिस्कशन कराना चाहिए।

श्री सभापति : आप डिस्कशन का नोटिस दीजिए या जब डिफेंस पर डिस्कशन होता है, तो उसमें इसको लीजिए।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : This is a very important subject. We need full support. ...*(Interruptions)*... It has a border with China. It deserves a discussion.

MR. CHAIRMAN : Thank you.

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI : The BRO is the sole stakeholder of road in border areas, just as the Minister said that 61 roads are under construction and only 16 have been completed. So, it is sole stakeholder in constructing roads in border areas. Sir, on the one hand, the progress in road construction is very slow and on the other hand, the quality, many times, is very, very poor because I come from that area. I, along with Mr. Rudy, have visited all the border areas like Chushul, Bumla, and all those areas. Will the Minister assure the House that in these strategically important areas the Government has a concrete programme to move fast and improve the quality of the works? If so, what are the details? And, secondly, I want to know if the Minister at all visited most of these places or even any one of these places. If he intends to visit and personally look after all these, the quality can be improved and the work can be completed.

SHRI M. M. PALLAM RAJU : Sir, I assure the hon. Member that we are taking all measures to speed up the construction of these roads and I have been blessed with a tenure of, so far, a little over six years in this Ministry; I have had the good fortune of visiting most of these areas and personally seeing the difficult conditions under which most of this work is carried on and, I am sure most of the Members who visited these areas, and specially the Passes, appreciate the very stringent and hard conditions that the Border Roads people work under. Despite the bad conditions and adverse weather conditions, our people work really very hard and they are making infrastructure in the harshest and hardest of conditions. As far as the measures are concerned, we have been conducting quarterly meetings of the Border Roads Development Board to assess the progress and over a period of years, we have taken a substantial number of measures, including procuring a lot of equipment to speed up the work in all these years. We have also delegated a lot of authority to Task Forces which are on the ground. We have also, definitely, taken a lot of measures to ensure that quality is maintained as far as construction is concerned.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, I would just like to add that the BRO is doing an outstanding job and we must appreciate of what it is doing. They man most of the sensitive roads connecting the border. Mr. Koshyari did mention that we all had an opportunity to visit most of these border roads, whether it is in Arunachal Pradesh or Sikkim or Himachal Pradesh or Uttarakhand, Leh or Ladakh. But, unfortunately, after going there, we found that it is manned by the Army and most of the workers are civilians who come from Bihar, Uttar Pradesh and from very far off places. The expertise to construct roads is inadequate. And, most of the contractors in the country do not want to go to these regions. It is a challenge for them. It is a challenge for the organisation. It is a challenge for the department since most of them hesitate in going there. It is so difficult working in Ley Ladakh and at other places. As a result, less than 50 per cent of the Budget of the Border Road Organisation and the Budget sanctioned for these areas is unutilized. I mean, there is a very low utilization of the Budget sanctioned, because of inadequacy of contractors in those regions who could go and work or the workers in that region. Now, this is a challenge which we need to understand from the hon. Minister as to how is he going to address the challenge of BRO and construction of good roads vis-a-vis China which has constructed the state-of-the-art roads across the border. So, this challenge we need to understand from the hon. Minister. I would like to know how he is going to address this.

SHRI M.M. PALLAM RAJU : Sir, comparison is usually drawn with China. Terrain across the border is a lot friendlier than the conditions that we face. It is the young Himalayan rock that we face in most of the mountainous States. There are also inclement weather conditions. If you look at, especially, the North-East, the construction window is only 4-5 months in a year. Along with that, we do have natural calamities like earthquake that we had in Sikkim last year, the downpour that we had in Ladakh and Arunachal Pradesh which tends to wash away a lot of construction that is done in this fragile terrain. Despite all this, we are making a good progress. We have inducted a lot of equipment which speeds up cutting of rock. We have formed additional Task Forces in areas like Arunachal Pradesh where we need to speed up the border roads work. We are conducting a lot of meetings, especially on-site, to understand the local conditions. There are also difficulties relating to procurement of material because of the stringent conditions. Despite this, we are making a good progress. This year, as far as GS Roads which pertains to the movement of the Army are concerned, we have utilized the entire Budget and we will do that in the coming years as well. And, we are improving the conditions for work.

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो सीमा सड़क संगठन है, उसके द्वारा कुछ काम लद्दाख और कारगिल में कराए जा रहे हैं। मैं अभी स्वयं लद्दाख और कारगिल क्षेत्र में गया था, वहां पर सड़कों की बहुत बुरी हालत है। काफी काम जो वर्षों से चल रहे हैं, वे अधूरे पड़े हुए हैं, यहां तक कि पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, कुरकुट जैसे

क्षेत्र हैं, वहां पर पूरी तरह से आवागमन की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो काम अधूरे हैं और जिन कामों को किया जाना चाहिए, विशेष तौर से कारगिल और लद्दाख क्षेत्र में तथा सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में, वे कब तक पूरे होंगे?

SHRI M.M. PALLAM RAJU : Sir, as far as Jammu & Kashmir is concerned, under the Prime Minister's Package, seven roads were identified for upgrading them to Class IX roads. Out of these, two have been completed and the work on the remaining is progressing very fast.

हथियारों का निर्माण करने वाली घरेलू/विदेशी कंपनियों को काली सूची में डाला जाना

*363. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा हथियारों का निर्माण करने वाली घरेलू और विदेशी कंपनियों को हाल ही में काली सूची में डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों को काली सूची में डाले जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन कंपनियों के साथ पहले हस्ताक्षर किए गए रक्षा सौदों को भी रद्द करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. अन्तोनी) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय ने निम्नलिखित फर्मों को उनके साथ आगे 10 वर्ष की अवधि के लिए व्यावसायिक लेन-देन करने के लिए, विवर्जित कर दिया है :

(i) मैसर्स सिंगापुर टैक्नोलॉलीज काइनेटिक्स लिमिटेड (एस.टी.के.)

(ii) मैसर्स इजराइल मिलिट्री इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई.एम.आई.)

(iii) मैसर्स टी.एस. किसन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

(iv) मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स लिमिटेड, लुधियाना

(v) मैसर्स, रीनमैटेल एयर डिफेंस (आर.ए.डी.), ज्यूरिख

(vi) मेसर्स कार्पोरेशन डिफेंस, रूस।

(ग) उपर्युक्त फर्मों को विवर्जित करने का निर्णय, उन्हें काली सूची में डाले जाने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई पर आधारित है, जो आयुध निर्माणी बोर्ड से अग्रिम भुगतान निर्मुक्त किए जाने सहित बोर्ड से व्यवसाय प्राप्त करने के लिए श्री सुदीप्त घोष, पूर्व महानिदेशक, आयुध निर्माणियां और अन्य को गैर-कानूनी परितोषण का भुगतान करने के लिए उनके विरुद्ध एकत्रित साक्ष्य पर आधारित थी।